

पिछली सरकार की 30 हजार किमी की तुलना में हमने 48 हजार किमी सड़कें बनाईं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए

जयपुर, 4 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़कों का निर्माण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण को निरंतर जांच की जाए एवं निम्नस्तरीय सड़क पर अधिकारी-

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जालौर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, कोटपुटली, अजमेर, बाँसवाड़ा के बीच कनेक्टिविटी को यथा शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा व अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता मौजूद थे।

समन्वय से तय समयसीमा में पूरा किया जाए। विकास एवं परियोजनाओं के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित हो। उन्होंने प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जालौर-झालावाड़, श्रीगंगानगर-कोटपुटली, अजमेर-बाँसवाड़ा के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रगतिरत कार्यों के बारे में अवगत

करवाते हुए बताया कि वर्तमान सरकार के 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में अब तक 33 हजार 195 करोड़ रुपये का व्यय कर 48 हजार 748 किमी लम्बाई में सड़कों का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। जिसमें से 17 हजार 934 किमी लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार में समान समयवधि के दौरान 13 हजार 400 करोड़ रुपये व्यय कर 30 हजार 641 किमी लम्बाई में सड़कों का

निर्माण कार्य ही किया गया था। वहीं, नवीन सड़कें भी केवल 4 हजार 671 किमी लम्बाई में निर्मित की गई थीं। साथ ही, केवल 280 गांव ही सड़कों से जुड़ पाए थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा व अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता सहित, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

‘ईरान वॉर से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ट्रंप प्रशासन का जोर देकर कहना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है, जबकि, दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच लगातार गोलीबारी जारी है और शांति वार्ता में वास्तविक प्रगति के संकेत नहीं दिख रहे हैं। डेमोक्रेट्स ट्रंप पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने फरवरी के अंत में कांग्रेस की अनुमति के बिना इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए थे। “युद्ध शक्तियाँ अधिनियम (वॉर पावर्स एक्ट) के तहत, अमेरिकी सेना को किसी भी संघर्ष में उतराने के बाद राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंजूरी लेने के लिए 60 दिन का समय होता है। वह समय सीमा कई सप्ताह पहले ही बीत चुकी है, और डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप अब कानून तोड़ रहे हैं। वाइट हाउस इस व्याख्या को

स्वीकार नहीं करता और उसका तर्क है कि अप्रैल में हुए संघर्ष-विराम के कारण यह समय सीमा अस्थायी रूप से रूक गई थी। लेकिन ट्रंप ने बार-बार हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी है, और इस सप्ताह तनाव और भी बढ़ गया है। रवातों-रात, अमेरिका ने बताया कि उसने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है और ईरान के एक जमीनी नियंत्रण केन्द्र पर हमला किया है, वहीं दूसरी ओर, तेहरान की सेनाओं ने खाड़ी क्षेत्र के कई पड़ोसी देशों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। ट्रंप का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन नेताओं ने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव ऐसे समय में अमेरिका को कमजोर करेगा, जब ईरान दबाव में है। लेकिन नवंबर में होने वाले मध्यवर्धि चुनावों से पहले युद्ध का राजनीतिक बोझ बढ़ने के कारण, उनकी नाराजगी भी अब अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी है।

सीजेपी को रैली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर ली है और लाखों समर्थक जुटा लिए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसकी तुलना हाल के वर्षों में दुनिया भर में उभरे उन ऑनलाइन आंदोलनों से कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति पर प्रभाव डाला था। इस सन्दर्भ में, 2010-12 के “अरब स्प्रिंग आंदोलन” और 2011 के “ऑक्सियाई वॉल स्ट्रीट” आंदोलन का भी उल्लेख किया जा रहा है। पिछले एक दशक में हॉंगकांग, ब्राज़ील और फिलीपींस से कई हैशटैग आंदोलनों की खबरें आई हैं। इसी तरह के युवा आंदोलनों ने, भारत के पड़ोसी देशों, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी बड़े राजनीतिक बदलावों को जन्म दिया है। अब यह देखना बाकी है कि दिपके और उनके सहयोगी अपने ऑनलाइन अभियान को जमीन पर वास्तविक जन आंदोलन में बदल पाते हैं या नहीं। सीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है, वे

काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इनमें धर्म-प्रधान का इस्तीफा, शासन में अधिक जवाबदेही, भ्रष्टाचार विरोधी कदम, गोदी मीडिया की जांच और राजनीतिक दल-बदल की जांच जैसी मांगें शामिल हैं। सीजेपी राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी वकालत करती है। इसके अलावा, पार्टी संस्थागत ईमानदारी को मजबूत करने और मतदाताओं को प्रभावित किए जाने की धारणाओं को कम करने की बात भी करती है।

चने की डाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रतिभाशाली दीक्षा कुशवाह उच्छ्रुत विद्यालय की कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं। वह शहर के शहर के फ्रीगंज स्थित एक आर्ट क्लास की भी छात्रा हैं।

खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले में नया मोड़

खान सर व कोचिंग सेंटर के गार्ड्स से पूछताछ की गई

पटना, 04 जून। खान सर के कोचिंग में हमले के मामले में अब उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं इसी बीच खान सर की कोचिंग जीएस ग्लोबल स्टडीज में हुए पधवार वाले दिन जो गार्ड ड्यूटी पर थे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की थी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर फायरिंग का आरोप है। दोनों

■ गार्ड्स के हथियारों की प्रामाणिकता भी जांची जा रही है। गार्ड्स के हथियारों की जांच कर लिए गए हैं और उनके लाइसेंस का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। खान सर के जिन दो बाँडिंगार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम प्रदीप और तालेश्वर हैं। खान सर से पुलिस ने उनकी

कोचिंग जीएस ग्लोबल स्टडीज में ही पूछताछ की है, ये पूछताछ काफी देर तक चली है। बताया जा रहा है कि अभी खान सर से और भी पूछताछ हो सकती है। इस मामले में पुलिस उनसे हर जानकारी ले रही है। दरअसल खान सर

की कोचिंग में हुए हंगामे में तोड़ फोड़ और फायरिंग की खबर के बाद, खान सर ने खरौंदा फायरिंग की बात से मना किया था। एफआईआर में भी फायरिंग की बात दर्ज नहीं थी। लेकिन खान सर के इनकार करने के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में हवा में दो लोग फायरिंग कर दिख रहे थे।

टीएमसी के विधायकों ने जो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अधिकतर बजटों के प्रति अपने गहरे रोप, यहाँ तक कि घुणा, को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी कहानियाँ भी सामने आ रही हैं कि चुनावी पराजय के बाद वरिष्ठतम विधायकों को भी इस विद्रोह तहस्ती के सम्मान में खड़े होकर तालियाँ बजाने के लिए मजबूर किया गया था। अगर ऐसा होता है, जैसा कि कई लोग मानते हैं कि यह भी समय की बात है, तो तृणमूल कांग्रेस के अधिकांश सांसदों का ऋतुव्रत बनजा गुट में जाना केवल उस व्यापक स्थिति का परिचायक होगा, जिससे पार्टी गुजर रही है। तृणमूल कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधि, एक के बाद एक, पार्टी और अपने पदों को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक नाम बिधानभवन नगर निगम की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती का है, जिन्होंने आज अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में पुष्टि की कि मौजूदा परिस्थितियों में काम करना अब संभव नहीं रहा है। हालाँकि उसी बिधानभवन क्षेत्र से निर्वाचित एक भाजपा विधायक ने दावा किया कि वे इसलिए पद छोड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कथित रूप से अत्यधिक बढ़ी हुई संपत्ति के उजागर

होने का डर है। बताया जाता है कि उनके पास 17-18 संपत्तियाँ हैं, जो वर्तमान में गैस्ट हाउस के रूप में संचालित हो रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने अन्य अचल संपत्तियाँ भी अर्जित की हैं। पत्रकारों से बात करते समय वे दशकों की जनसेवा के बाद पद छोड़ने की बात करते हुए धातुक हो गई और उनकी आँखों में आँसू थे। उदाहरण के लिए, एनआईए पूरे दिन तृणमूल के कुख्यात बाहुबली सौकत मोल्ला को पकड़ने की कोशिश करती रही। मोल्ला पर चुनाव से पहले कोलकाता के निकट भांगड़ क्षेत्र में हुए एक कथित बम हमले में शामिल होने का संदेह है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। सौकत मोल्ला की तलाश के दौरान, एनआईए की उनके विशाल संपत्ति समग्रण का भी पता चला, जिसमें मकान, कैफे, रेस्तराँ, इमारतें तथा कथित रूप से एक बारहमासी नदी

की भूमि पर अवैध कब्जा शामिल है। आरोप है कि सौकत ने नदी के पानी का प्रवाह रोककर, उसके किनारे विशाल क्षेत्र में भूमि विकसित कर ली थी, जिसका क्षेत्रफल हजारों एकड़ बताया जाता है। उनके बेटे ने उस भूमि पर एक कैफे बना लिया है और उनके भाई उसी क्षेत्र में एक पॉप सितारा होटल का निर्माण कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण कथित रूप से हत्या और धमकी के डर से विरोध नहीं कर सके। कहा जाता है कि स्थानीय पुलिस भी सौकत मोल्ला और उनके पुत्र के प्रभाव में थी। एनआईए ने अब सौकत को 8 जून को तलब किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वे उपस्थित नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में अब कथित भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, और दबंगों तथा पूर्व शासन - संरक्षित लोगों द्वारा किये गये अत्याचारों को लेकर व्यापक आक्रोश और विरोध दिखाई दे रहा है। ऐसे मामलों की संख्या इतनी अधिक बताई जा रही है कि किसी भी बेहद सर्म्पत्त व निष्पक्ष सरकार के लिए भी इनसे एक साथ निपटना मुश्किल है। जनता की अपेक्षाएं बहुत ऊँची हैं और यह एक पहेली बनी हुई है कि इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा।

केरल में मानसून ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कारण दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें पड़ने का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद तापमान में आई गिरावट से लोग राहत महसूस कर रहे हैं और शूलसा ने वाली गर्मी से छुटकारा मिलने पर संतोष जता रहे हैं। स्थिति को देखते हुए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 4 जून से 5 जून तक के लिए क्षेत्र में पुनः “थेलो अलर्ट” जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो दिनों तक दिल्ली-पनसीआर में आसमान मुख्यतः बादलों से ढका रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार, इस अवधि में हल्की से मध्यम बारिश, बार-बार गरज के साथ छोटें पड़ने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएँ चलने की संभावना है, विशेषकर दिन के उत्तरार्ध में। दक्षिण भारत में मानसून के समय से पहले पहुंचने के कारण, उत्तर भारत के वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ गई है, जिससे प्री-मानसून गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। जैसे-जैसे यह नम हवा उत्तर की ओर बढ़ रही है, वह दिल्ली-पनसीआर की स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के साथ मिलकर तेज हवाओं, धूलभरी आंधियों और अनियमित गरज-चमक वाले तूफानों

मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगी, पांच की मौत

मुजफ्फरपुर, 04 जून। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रसाद अस्पताल में लगी भीषण आग की घटना में अब तक 05 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने इसकी पुष्टि की है। आग तड़के करीब 3 बजे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी थी। इसके बाद देखते ही देखते पूरे अस्पताल में धुआँ फैल गया। इससे अस्पताल परिसर के अंदर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर

■ अभी तक की जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है।

पहुँची दमकल टीम ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घटना में अब तक 05 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्मार्ट चौधरी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुःख है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग एमपी से राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित

भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, मणिपुर व राजस्थान से प्रत्याशियों की घोषणा की

नई दिल्ली, 04 जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केन्द्रीय चुनाव समिति ने पांच राज्यों में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव-2026 तथा ओडिशा में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दो सीटों से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ संगठनात्मक नेता रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा, बीजद छोड़ कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए देवाशीष सामंतराय को ओडिशा उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से गुजरात की अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान की 10 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव और ओडिशा की एक

■ अरुणाचल से ताई तागाक, गुजरात से राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, राजस्थान से डॉ. सतीश पूनिया और अलका गुर्जर, मणिपुर से शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है।

सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। इसमें अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक, गुजरात से राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया, मध्य प्रदेश से मणिपुर से ए शारदा देवी तथा राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पूनिया को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाए गए तरुण चुग भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन के प्रमुख रणनीतिकारों

में गिने जाते हैं। पंजाब के अमृतसर से आने वाले चुग जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना सहित कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। दूसरे उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल लंबे समय से मध्य प्रदेश भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं। वे वर्तमान में प्रदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद, उसी दिन मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।

मालविया नगर अग्निकांड के परिजनों को 10 लाख रु. की सहायता

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सभी मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

नई दिल्ली, 04 जून। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मालवीय नगर अग्निकांड में घायल लोगों का हाल चाल जानने के लिए साकेत स्थित अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की, उनके परिजनों से बात की और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं, गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिन मृतकों के परिजन अन्य राज्यों या विदेशों में रहते हैं, उनके

■ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के होटलों, व्यावसायिक परिसरों व अन्य सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिये।

पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके घर तक पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ तुरंत की जाएँ। अस्पताल में भर्ती घायलों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें ढाँढ संभालते हुए कहा कि दिल्ली सरकार उनके साथ है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने चिकित्सकों से प्रत्येक मरीज की स्थिति की व्यक्तिगत जानकारी ली और उपचार प्रक्रिया की निरंतर निगरानी बनाए रखने

के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मरीज गंभीर स्थिति में हैं और कुछ को वैटिलेटर पर रखा गया है। प्रभावितों में, भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, कैमरून, लीबिया सहित अन्य देशों के नागरिक भी हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और विदेशी नागरिकों के मामलों में भी आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया

जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी में सुरक्षा संबंधी कई गंभीर कमियाँ सामने आई हैं। कई भवनों में आपातकालीन निकास मार्ग, फायर सेफ्टी सिस्टम और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाती। उन्होंने संबंधित विभागों को घटना की विस्तृत जांच कराने और राजधानी के होटलों, व्यावसायिक परिसरों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां भी लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होगी, वहां जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

‘हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेगा’

बेरूत, 04 जून। इजरायल और लेबनान के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम समझौते को लेकर नया विवाद खड़ा हो चुका है। लेबनान के शक्तिशाली संगठन हिज्बुल्लाह ने इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा है कि मौजूदा प्रस्ताव उसे स्वीकार्य नहीं है और इससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। हिज्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने स्पष्ट किया है कि जब तक दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी बनी रहेगी, तब तक उनका संगठन प्रतिरोध जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी युद्धविराम की शर्त यह होनी चाहिए कि इजरायल पूरी तरह लेबनानी क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाए और सैन्य कार्रवाई पूरी तरह समाप्त करे। कासिम ने लेबनानी सरकार और इजरायल के बीच चल रही बातचीत पर भी सवाल उठाए।

इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके

चेन्नई, 04 जून। द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डीएमके) ने आठ जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग न लेने का फैसला किया है। पार्टी ने कांग्रेस पर तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। बता दें कि मीडिया प्रस्ताव उसे स्वीकार्य नहीं है और विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस, डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके के साथ गठबंधन में शामिल हो गई थी, जिसे डीएमके ने धोखा करार दिया था। बता दें कि डीएमके इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगियों में से एक थी।

आज पत्ने खोलेंगे अन्नामलाई

चेन्नई, 04 जून। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रमुख अश्वक के अन्नामलाई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने शुक्रवार, पांच जून 2026 को दोपहर 12:00 बजे एक बड़े सोशल मीडिया संबोधन का घोषणा की है। इस एक एलान ने राजनीतिक हलकों में अटकलें का बाजार बेहद गरम कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक अब उनके अगले कदम को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अन्नामलाई भाजपा से दूरी बनाने या पार्टी छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहां उन्होंने केन्द्रीय कार्यकारी भी अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन मोदी समेत शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे केन्द्रीय आलाकमान को अपना इस्तीफा भी सौंप चुके हैं।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पुलिस ने कहा कि वे एफआईआर की कॉपी देंगे। तीन जून को दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की धुं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे।

बयान में डीएमके ने कहा कि वह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। पार्टी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, नगरिकता, संसोधन अधिनियम (सीएए), चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, वन नेशन, वन इलेक्शन

प्रस्ताव, वक्फ अधिनियम में संशोधन और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में बदलाव जैसे मुद्दों पर अपने विरोध का उल्लेख किया। डीएमके ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु चुनावों के बाद कांग्रेस के व्यवहार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरा नाराजगी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अधिवक्ता एस.एस.होरा ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी को दिया हुआ ठेका बिना किसी कारण और सुनवाई किए जेडीए के लिए वापस लिया है, जबकि कंपनी ने ड्राइंग्स और डिजाइन तैयार कर अनुमोदन के लिए पेश कर दिए थे। कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए थे, लेकिन जरूरी अनुमति या व साइट पर जमीन मुहैया नहीं करवाने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन कारणों की वजह से लिया गया है, जो याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने बताया कि एमएनआईटी व ओटीएस द्वारा प्रोजेक्ट बदलने के 2023 में दिये गए ज्ञापनों पर जेडीए के अधिकारियों ने नया प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। अधिवक्ता एस.एस. होरा ने कहा कि डॉ.पी.पी.आर. के लिए टेंडर निकालना पहले से तैयार डी.पी.आर. और प्रोजेक्ट को निरस्त करने जैसा है, जबकि कंपनी ने 64 बार पत्र लिखकर प्रोजेक्ट के ड्राइंग अप्रुवल के लिए लिखा था।

हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रकार में प्रथमदरजाया प्रभारी अधिकारी की ओर से अदालत में गलत बयानबाजी की गई है, जिसके तथ्य रिकॉर्ड से अलग पाए गए हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से काम करना होगा। राजनीतिक कारणों से सरकार अपने संविदात्मक दायित्वों से बच नहीं सकती है। जेडीए एक तरफ कह रहा है कि कंपनी की वजह से देरी हुई, लेकिन दूसरी ओर जेडीए ने बिना ज्ञापनों लगाए कंपनी को उसकी बैंक गारंटी लौटा दी। यह कृत्य अदालत को गुमराह करने वाला है।

याचिका में कहा गया कि जेडीए ने ओटीएस चौराहे को सिग्नल फ्री और सौंदर्यकरण कराने को लेकर टेंडर निकाले थे। याचिकाकर्ता जेसीएल इंफ्रा प्रा. लि. को टेंडर मिलने के बाद कंपनी को 6 जनवरी 2023 से 5 जनवरी 2024 तक काम पूरा करना था। इसी बीच सरकार बदलने के बाद जेडीए ने अनुबंध की शर्तों का हवाला देते हुए 24 अप्रैल 2024 को ठेका वापस ले लिया। इसके बाद 16 दिसंबर को याचिकाकर्ता की बैंक गारंटी भी वापस कर दी। वहीं

मौके देने के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर नियमानुसार ठेका निरस्त किया गया है। इसके अलावा अब वहां 184 करोड़ रुपये के बजट 83 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर बनना है। जेडीए की तरफ से कहा गया कि जेसीएल इंफ्रा ने समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जरूरी डिमांड व ड्राइंग जेडीए को उपलब्ध नहीं कराए थे और अनुबंध के अनुसार, उपयुक्त अधिकारी (स्थानीय एक्सपर्ट) ने समयबद्धि पूरी होने के बाद उचित प्रक्रिया से अनुबंध निरस्त किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फ्लाईओवर बनाने के लिए जारी डीपीआर को रद्द कर पुराने अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है।

ओटीएस चौराहे पर फ्लाईओवर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रकार में प्रथमदरजाया प्रभारी अधिकारी की ओर से अदालत में गलत बयानबाजी की गई है, जिसके तथ्य रिकॉर्ड से अलग पाए गए हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से काम करना होगा। राजनीतिक कारणों से सरकार अपने संविदात्मक दायित्वों से बच नहीं सकती है। जेडीए एक तरफ कह रहा है कि कंपनी की वजह से देरी हुई, लेकिन दूसरी ओर जेडीए ने बिना ज्ञापनों लगाए कंपनी को उसकी बैंक गारंटी लौटा दी। यह कृत्य अदालत को गुमराह करने वाला है।

अधिवक्ता एस.एस.होरा ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी को दिया हुआ ठेका बिना किसी कारण और सुनवाई किए जेडीए के लिए वापस लिया है, जबकि कंपनी ने ड्राइंग्स और डिजाइन तैयार कर अनुमोदन के लिए पेश कर दिए थे। कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए थे, लेकिन जरूरी अनुमति या व साइट पर जमीन मुहैया नहीं करवाने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन कारणों की वजह से लिया गया है, जो याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने बताया कि एमएनआईटी व ओटीएस द्वारा प्रोजेक्ट बदलने के 2023 में दिये गए ज्ञापनों पर जेडीए के अधिकारियों ने नया प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। अधिवक्ता एस.एस. होरा ने कहा कि डॉ.पी.पी.आर. के लिए टेंडर निकालना पहले से तैयार डी.पी.आर. और प्रोजेक्ट को निरस्त करने जैसा है, जबकि कंपनी ने 64 बार पत्र लिखकर प्रोजेक्ट के ड्राइंग अप्रुवल के लिए लिखा था।

उपर जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि याचिकाकर्ता को कई

जल जीवन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अलावा, जितेंद्र शर्मा, मुकेश गोयल और संजीव गुप्ता के फरार होने के चलते अदालत ने उनके गिरफ्तारी के स्थायी वारंट जारी कर रखे हैं।